Saarth
E-Journal of Research

ISSN NO: 2395-339X

नई शिक्षा नीति 2020

डॉ. कल्पना निरंजन
एसोसिएट प्रॉफेसर (अर्थशास्त्र विभाग)
आर्यकन्या पी.जी कॉलेज, झाँसी

यदि भारत की शिक्षा नीति से जुड़ा इतिहास उठा कर देखा जाये तो हम पाते हैं कि भारत में शिक्ष्ज्ञा हमेशा केंद्र और राज्य के लिए महत्वपूर्ण विषय रही है। शिक्षा प्रणाणी के साथ नए प्रयोग करना और इसमें खुल कर निवेश करना भारत की एक परम्परा है। भारत में अब तक आई रह शिक्षा नीति ने धर्म और राजनीति से ऊपर शिक्षा को हमेशा सर्वोपरि रखा है। इन नीतियों का उद्देश्य रहा कि रह हाल में गुणवतापूर्ण शिक्षा सभी तक बिना किसी बाधा के पहुँचे क्योंकि ये हर भारतीय का मौलिक अधिकार है। इसके अलावा ये राज्य की जिम्मेदारी है कि वे हर छात्र की मदद करें जो शिक्षा के क्षेत्र में कुछ विशिष्ट करने की योग्यता रखता हो।

इसी विचार और उद्देश्य जनित व्यक्तव्य (स्टेटमेंट ऑफ पर्पस) के अंतर्गत शिक्षा नीति हमेशा 6–12 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए मुक्त बुनियादी स्कूली शिक्षा प्रदान करने के लिए कटिबद्ध है।

ये नीति चाहती है कि माध्यमिक विद्यालय को अनिवार्य बनाया जाए और इसके लिए आवश्यक आर्थिक संसाधन अनुदान और ऋण की शक्ल में जरूरमंदों तक पहुंचाए जाएँ।

भारत की पुरानी शिक्षा नीति को नयी जरूरतों के सांचे में ढाला जाए और फिर उन पर 21वीं सदी की रोजगारपरकता की मोहर लगाकर फिर से मैदान में उतारा जाए। इस तरह की आवश्यकता को लम्बे समय से महसूस किया जा रहा था। पिछले दिनों जब नयी शिक्षा नीति की घोषणा की गयी तो ज्यादातर विशेषज्ञों की राय थी कि इसमें ज्यादातर बदलाव शिक्षण को अधिक कुशल बनाने के लिए और वर्तमान में व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकने के लिए किये गए हैं।

पुरानी नीति से तुलना करे तो हम पाते हैं कि नयी नीति में कई आमूल–चूल परिवर्तन किये गए हैं, जैसे की स्कूल अब सरकार द्वारा केंद्रीय रूप से नहीं चलाए जाएंगे, बल्कि जिला स्तरों में विभाजित किए जाएंगे, प्रत्येक जिले में स्कूल, शासी निकाय का अपना सेट होगा। यह शिक्षा के अधिक निजीकरण और छात्रों की जरूरतों और आकांक्षाओं की बेहतर समझ की अनुमति देगा।

नई शिक्षा नीति का उद्देश्य देश के छात्रों को बेहतर गुणवत्ता वाली शिक्षा देना है। यह नीति स्पष्ट करती है कि शिक्षकों को अधिक जवाबदेह बनाने के लिए नए तरीके ईजाद किये जाए साथ ही साथ रटने की जगह रचनात्मक सोच पर जोर दिया जाए जहाँ पर कोई छात्र प्रश्न का उत्तर देने के लिए शिक्षा के संप्रयोग को सुनिश्चित करे।

Saarth
E-Journal of Research
ISSN NO: 2395-339X

ये नीति पूरी तरह से शिक्षा क्षेत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार को निम्नतम स्तर पर लाकर उसका उन्मूलन करना चाहती है। यदि संक्षिप्त में कहा जाए तो हम कह सकते है कि वर्तमान शिक्षा नीति सही समय पर उठाया गया ऐसा कदम है जो निश्चय ही शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करेगा।

कई शिक्षाविदों का मानना है कि ये शिक्षानीति एक सकारात्मक बदलाव है जिसके दूरगागी परिणाम दो स्तरों पर नजर आयेंगे, पहला ये नीति अच्छे और योग्य नागरिकों का सृजन करेगी और दूसरा, ये नीति देश के नागरिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए पर्यावरण तंत्र का निर्माण करेगी।

नयी शिक्षा नीति पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अगुआई में पिछले काफी दिनों से काम चल रहा था, एक उच्च स्तरीय विशिष्ट कार्य–बल का गठन किया गया। इस विशिष्ट कार्य–बल ने पुरानी नीति में कुछ परिवर्तन की सिफारिश की और साथ ही साथ कुछ नए नियम भी जोड़े। नयी नीति का उद्देश्य सस्ती कीमत पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना और औपचारिक प्रशिक्षण के साथ व्यावसायिक प्रशिक्षण को एकीकृत करना है। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के अनुसार ''नयी शिक्षा नीति के गठन से पूर्व समाज के सभी वर्गों के 2.25 लाख लोगों के सुझाव के लिए गए और उनका व्यापक विश्लेषण किया गया।'' आशा की जा रही है कि नए भारत के निर्माण में ''नई शिक्षा शिक्षा नीति 2020'' मील का पत्थर साबित होगी।

एक रोजगार योग्य युवा बनाने के लिए स्कूली शिक्षा पहली प्रयोगशाला है, इस विचार के प्रतिपादन कू लिए कोर्स के प्रतिरूपण और परीक्षा के तरीकों में परिवर्तन की भी सिफारिश की गयी है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अकादमिक ज्ञान के साथ–साथ पाठ्यक्रम में कौशल विकास को भी जोड़ा जाएगा। इसकी वजह से छात्रों के अन्दर एक तरह की वैज्ञानिक सोच विकसित होगी जो उम्र उनके काम आएगी। ये सोच उन्हें काम और ज्ञान की गुणवत्ता और उत्तमता से हमेशा जोड़ रखेगी।

ये शिक्षा नीति इस प्रकार कार्य करेगी जहाँ पर किसी भी छात्र के सम्मुख समय से पूर्व कॉलेज या स्कूल छोड़ने के कम से कम कारण उत्पन्न हो इस शिक्षा की मदद से विकसित किये गए प्रशिक्षण जीवन पर्यंत छात्रों का मार्गदर्शन करते रहेंगे।

नयी शिक्षा नीति में प्रस्तावित परिवर्तनों का उद्देश्य सिर्फ अकादिम नहीं है, नयी नीति उन्हें अच्छे आचरण पर चलने की शिक्षा भी देगी। इसके लिए पाठ्यक्रम में कुछ अध्याय अलग से भी जोड़े जायेगे जिनका उद्देश्य होगा छात्रों को अच्छे नैतिक मूल्यों के बारे में जानकारी देना।

कई विशेषज्ञ ये भी मानते हैं कि नयी शिक्षा नीति पुरानी शिक्षा को नए युग से जोड़ने का प्रयास है जहाँ पर छात्रों को वैश्विक परिदृश्य के लिए प्रासंगिक कौशल और ज्ञान से लैस किया जायेगा।

इसकी वजह से वे भारत के बारह भी आराम से रोजगार प्राप्त कर सकेंगे। ये परिवर्तन छात्रों को अध्ययन और अध्यवसाय के विभिन्न विकल्पों की खोज का अवसर देंगे ताकि वे अपनी शिक्षा को अद्योग की मांग के अनुरूप परिवर्धित कर सकें।

इस नीति में किये गए बदलाव छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के मौलिक अधिकारों को मुख्यधारा में लायेंगे ताकि शिक्षा का निष्पादन गंभीरता एवं जिम्मेदारी के साथ किया जा सके।

Saarth
E-Journal of Research
ISSN NO: 2395-339X

नीति के प्राथमिक दस्तवेजों में, खेल एवं शारीरिक शिक्षा पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता समझाई गयी है। इस नीति के प्रमुख संकेन्द्रण क्षेत्रों को निम्न रूप से परिभाषित किया जा सकता है।

• सीखने की गतिविधियों में संलग्न होना और अपनी जरूरत के हिसाब से प्रासंगिक पाठयक्रम चुनना रह छात्र का मौलिक अधिकार है।

• सीखने के लिए वातावरण का निर्माण एवं उन परिस्थितियों का सृजन जहाँ पर अनुभव जनित शिक्षा का प्रादुर्भाव हो।

• शिक्षण एवं अध्यापन के लिए आवश्यक संसाधनों तक शिक्षकों एवं छात्रों की पहुँच।

• शिक्षा के लिए आदर्श वातावरण का निर्माण जहाँ पर मूल्यांकन के तरीकों को उद्योगों की मांग के अनुरूप नए स्तर पर लाना।

• शिक्षा प्रणाली से जुड़े सभी हितधारको की उचित भागीदारी एवं जवाबदारी तय करने के लिए दस्तावेजों का चयन।

• शिक्षा प्रणाली से जुड़े सभी हितधारकों को ऐसा मंच प्रदान करना जहाँ पर वे वर्तमान आवश्यकताओं के अनुकूल शिक्षा के बाह्म निर्गम को ढाल सकें।

संक्षिप्त में ये कहा जा सकता है कि शिक्षा नीति में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कई बदलावों को मंजूरी दी है। इन परिवर्तनों का मूल उद्देश्य है संपूर्ण शिक्षा प्रणाली में बदलाव लाना और इसे देश, काल और वातावरण की वर्तमान आवश्यकताओं के अनुकुल बनाना है।

नयी शिक्षा नीति की प्रासंगिकता

अघोषित रूप से 1.3 अरब की आबादी, 16 राजपत्रिक भाषाए एवं 26 राज्यों में बिखरी सांस्कृतिक विविधता, ऐसे किसी देश को शिक्षा नीति के जरिए एक सूत्र में पिराना हमेशा से एक दुष्कर कार्य रहा है। मगर नयी शिक्षा नीति की पहुँच सार्वभौमिक है। इसमें तथ्यों और प्रसंगों की जगह मनोविज्ञान को ज्यादा अधिमान दिया गया है। देश में स्कूल जाने वाले छात्रों की एक बड़ी संख्या है, जो जीवन के सभी क्षेत्रों से आते हैं और नई चीजें सीखना चाहते हैं। ये शिक्षा नीति उनकी इस विविधता को प्रतिबिंबित तो करती है साथ ही उन्हें एक सुत्र में भी पिरोती है जहाँ पर रोजगार प्रतिस्पर्धा के मैदान में कोई भी किसी से पीछे ना रहे।

इस शिक्षा नीति को लागू करते वक्त सरकार को ये ध्यान रखना होगा कि करदाताओं का पैसा बुद्धिमानी से खर्च किया जाए। भारत ने हाल के वर्षों में साक्षरता दर में सुधार की दिशा में नए कीर्तिमान स्थापित किये हैं, मगर अब बारी है, इन कीर्तिमानों को अगले स्तर पर ले जाने की जहाँ साक्षरों एवं नव साक्षरों को रोजगार के उचित अवसर अपलब्ध करवाए जाए और शिक्षा उनमें एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करे।

ये शिक्षा नीति अभी प्राथमिक स्तर पर तो समीचीन प्रतीत होती है मगर स्वास्थ्य, कृषि और अनुसंधान जैसे बहुत सारे विषय अभी भी बाकी है जिन्हें मुख्य धारा में शामिल किया जाना अभी बाकी है।

Saarth
E-Journal of Research
ISSN NO: 2395-339X

माना जात है कि अगले पांच वर्षों के दौरान भारत को अपनी जनसांख्यिकी और आर्थिक स्थितियों में बड़े बदलाव देखने पड़े सकते हैं। साथ ही साथ बदलते राजनीतिक परिदृश्य आधुनिकीरण और अपभोक्तावाद भी एक नयी सामाजिक व्यवस्था का गठन करेंगे। विभिन्न सामाजिक स्तरों के उदय एवं विकास को ये शिक्षा नीति प्रणाली काफी हद तक नियंत्रित कर सकती है और एक ऐसे वर्तमान की रचना कर सकती है जो भविष्य को आदर्श स्थितियों में पहुँचा सके।

नयी शिक्षा नीति को समझने के लिए लक्ष्य–उन्मुख शिक्ष के विषय वस्तु को समझना आवश्यक है, वर्तमान में भारत में लक्ष्य–उन्मुख शिक्षा का दौर चल पड़ा है। कोटा फैक्ट्री, कोचिंग इंस्टिट्यूट और प्राइवेट ट्यूशन इसी लक्ष्य–उन्मुख शिक्षा का कुत्सित उदाहरण है। इसके अलावा अब तो सरकार ने भी माना है कि भारत में इस समय शिक्षा माफिया भी कार्यरत हैं। ये माफिया शिक्षा तो नहीं मगर शिक्षा के फर्जी प्रमाणमत्र आपको जरूर दिलवा सकते हैं।

यदि वर्तमान शिक्षानीति की तुलना हम पिछली शिक्षा नीतियों से करे तो हम पाते हैं कि पिछली सरकारे काफी रूढ़िवादी थी एवं शिक्षा में सुधार करते वक्त उन हिस्सों को नहीं सुधार पाई जिनका लाभ शिक्षा माफिया उठाते हैं। मगर नयी शिक्षा नीति में कई ऐसे बिंदु हैं जहाँ पर इन शिक्षा माफियाओं को मिलने वाले अवसरों का गला घोंटा गया है। सबसे बड़ी बात ये है कि इस बार पढ़ाने से ज्यादा प्रयोग या अनुभव पर संकेन्द्रण किया गया है।

अधिगम नहीं चिंतनशील अधिगम के मन्त्र को प्रमुखता से प्रचारित करती है वर्तमान शिक्षा नीति।

चिंतनशील अधिगम एक व्यक्तिगत अनुभव होता है, इस वजह से नकल और बेईमानी की आवश्यकता कम हो जाती है। छात्र अपने आप विचार कर सकता और उत्तर लिख सकता है, जानकारी से ज्यादा सोच को महत्ता मिलने की वजह से ये नीति शिक्षा माफिया द्वारा फैलाये गए मकडजाल से छात्रों को बाहर निकालने में कामयाब रहेगी।

शिक्षा नीति के क्रांतिकारी बदलाव

एनईपी 2020 (NEP) स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों प्री–स्कूल से माध्यमिक स्तर तक सबके लिए एक समान पहुं सुनिश्चित करने पर जोर देती है, अब 10+2 ढांचे की जगह 5+3+4 का नया पाठ्यक्रम संरचना लागू होगा। वहीं स्कूल छोड़ चुके बच्चों को फिर से मुख्या धारा में शामिल करने के लिए स्कूल के बुनियादी ढांचे का विकास और नवीन शिक्षा केंद्रों की स्थापना की जाएगी।

1. नई शिक्षा नीति के तहत अब पांचती तक के छात्रों को मातृ भाषा, स्थानीय भाषा और राष्ट्र भाषा में ही पढ़ाया जाएगा।

2. बाकी विषय चाहे वे अंग्रेजी ही क्यों न हो, एक विषय के तौर पर पढ़ाया जाएगा।

3. अब सिर्फ 12वीं में बोर्ड की परीक्षा देनी होगी, जबकि इससे पहले 10वीं बोर्ड की परीक्षा देनी अनिवार्य होता था, जो अब नहीं होगा।

Saarth
E-Journal of Research
ISSN NO: 2395-339X

4. कॉलेज की डिग्री 3 औ 4 साल की होगी यानि कि ग्रेजुएशन के पहले साल पर सर्टिफिकेट, दूसरे साल पर डिप्लोमा और तीसरे साल में डिग्री मिलेगी।

5. 3 साल की डिग्री उन छात्रों के लिए है जिन्हें हायर एजुकेशन नहीं लेना है वहीं हायर एजुकेशन करने वाले छात्रों को 4 साल की डिग्री करनी होगी।

6. 4 साल की डिग्री करने वाले छात्र एक साल में MA कर सकेंगे।

7. अब छात्रों को MPhil नहीं करना होगा बल्कि MA अब सीधे PHD कर सकेंगे।

8. नई शिक्षा नीति के तहत कोई छात्र एक कोर्स के बीच में अगर कोई दूसरा कोर्स करना चाहे तो पहले कोर्स से सीमित समय के लिए ब्रेक लेकर वह दूसरा कोर्स कर सकता है।

फौरी तौर पर हम ये कह सकते हैं कि नयी शिक्षा नीति में शिक्षा के क्षेत्र में एक लचीलापन लेकर आ रही है। इस लचीलेपन की वजह से आने वाली पीढ़ी के छात्र सबसे पहले तो मुख्य विषयों के साथ जीवन के अन्य पहलूओं पर भी ध्यान दे सकेंगे और दूसरी बात, पिछले तंत्र में सिर्फ बच्चों की अकादमिक क्षमताओं पर ध्यान दिया जाता था। मगर इस तंत्र में परिणाम अध्यापको और माता पिता को हर कदम बच्चे की तरक्की की रिपोर्ट दे सकेते हैं। उच्च शिक्षा की राह का भी सरलीकरण किया गया है और सबसे बड़ी बात है कि ये शिक्षा नीति छात्रों को मुख्य पाठ्यक्रम के बीच में छोटे–छोटे पाठ्यक्रम पढ़ने की आजादी भी देती है। इस तरह का प्रावधान लाने से अब छात्र मुख्य कोर्स करते–करते ब्रेक लेकर छोटे कोर्स भी कर पायेंगे।

References

www.indiatoday.in/education-today/featurephilia/story/national-education-policy-what-education-experts-are-saying-about-nep-2020-1706139-2020-07-30.

https://indianexpress.com/article/explained/reading-new-education-policy-india-schools-colleges-6531603/.

https://timesofindia.indiatimes.com/city/hubballi/experts-academicians-hail-new-education-policy/articleshow/77320737.cms.

www.hindustantimes.com/education/nep-2020-implementation-of-new-education-policy-in-our-education-system/story-bw4OiekFCamI7NPoNkgAoJ.html.